कौशल विकास और निजी क्षेत्र

प्रमोद भसीन

ऐसे समय में, निजी क्षेत्र की भागीदारी और भूमिका बिल्कुल अपरिहार्य है और कौशल विकास के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा इसी तरह के प्रयासों के जरिए समर्थन किया जाना चाहिए। यह समय भारत के निजी क्षेत्र के लिए है, कि वे इन प्रमुख सरकारी पहलों से नजदीकी से जुड़कर इन्हें आगे ले जाएं। हमारी जनसांख्यिकी, हमें दुनिया को कार्य बल प्रदान करने में बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम निजी क्षेत्र और सरकार के बीच एक उत्कृष्ट भागीदारी का निर्माण करें। हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन संयुक्त रूप से हम इस कमजोरी को भारत के लिए एक बड़ी सफलता और ताकत बना सकते हैं

कम श्रम लागत और प्रचुर प्रतिभा संपन्न होना भारत का विशिष्ट लक्षण है जिसने स्पष्ट रूप से एक *ज्ञान आधारित देश* के रूप में इसकी वैश्विक स्थिति और प्रतिस्पर्धात्मकता को स्थापित किया है। वर्ष 2030 तक भारत में कार्यकारी बल की संख्या एक अरब के करीब होगी। ऐसे में भारत के भविष्य को तेज गति देने और आर्थिक विकास हेतु यहां के लोगों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण मुहैया करना एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। इसके अलावा, भारत की स्थिति को एक प्रभावी कार्यशील अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत करने के लिए मानव संसाधन को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना आज समय की जरूरत है और यह अपरिहार्य बन गया है कि हम एक देश के रूप में यह अहसास करें और इसमें निवेश करें। कौशल विकास और प्रशिक्षण पर काफी जोर देने के बावजूद अभी भी यहां कुशल श्रम शक्ति की कमी है। अत: मानव संसाधन विकास को देश के समग्र विकास के लिए तेजी से महत्व मिलेगा।

2025 तक भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश का वैश्विक कार्यबल में 35 प्रतिशत योगदान देने की उम्मीद है। यह एक व्यापक आर्थिक संपदा है और हमारी सबसे बड़ी ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। हमें अपने मिशन और क्षमता को पूरा करने के लिए इसका अत्यधिक लाभ उठाना चाहिए। हालांकि, इस विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ लेने के लिए हमें बड़े पैमाने पर कौशल विकास और रोजगार पहल की आवश्यकता है। पिछले वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,500 करोड़ रुपये की योजाना *कुशल भारत अभियान* का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य 2022 तक विभिन्न कौशलों में 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना है। इस पहल में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए 2015 राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) योजना और कौशल ऋण योजना आदि शामिल हैं। जहां, कौशल विकास पर निस्संदेह मजबूती से ध्यान केंद्रित है, वहीं 2022 तक 500 मिलियन (50 करोड़) लोगों को कुशल बनाने के लक्ष्य को हम कैसे पूरा करेंगे, इस बारे में अभी भी थोड़ी अस्पष्टता है।

भारत ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, जिसके कारण कौशल में भारी कमी आई। जब तीव्र आर्थिक विकास ने भारत में कुशल श्रमिकों की मांग को दस गुणा तक बढ़ा दिया, तब भारत के सभी आर्थिक क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की भारी कमी उजागर हुई। हमारी समस्या की जड़ रोजगार की कमी नहीं है, अपितु ऐसे रोजगारपरक, कुशल प्रतिभा की कमी है जो तेजी से फैल रहे उद्योग की जरूरत को पूरा कर सके। भारत में प्रतिवर्ष 30 लाख स्नातक नौकरी के लिए तैयार होते हैं, उनमें से केवल पांच लाख युवाओं में ही नौकरी पाने की क्षमता होती है। आईटी, बीएफएसआई, हेल्थकेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, ऑटो और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं सहित अन्य क्षेत्र में श्रमशक्ति की भारी कमी है।

हाल ही में एक आंकड़े के अनुसार, सिर्फ 10 वयस्कों में से एक में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कही है। राष्ट्रीय नमूना

लेखक बीपीओ कंपनी जेनपैक्ट के चेयरमैन, संस्थापक तथा पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य देशों में वित्तीय, प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ सेवाओं में उनका विशाल अनुभव है। ईमेल: zorema.darkim@skillsacademy.co.in

सर्वेक्षण कार्यालय ने इस साल के शुरू में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर 2011-12 राउंड के आधार पर आंकड़े जारी किए थे।

इन आकड़ों से पता चलता है कि 15-59 वर्ष की आयु वर्ग में, केवल 2.2 प्रतिशत लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और 8.6 प्रतिशत लोगों ने गैर-औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कही है। यही नहीं, व्यावसायिक प्रशिक्षण की दर बमुश्किल बढ़ी है, 2004-05 और 2011-12 में जब अंतिम बार आंकड़े एकत्रित किए गए। वर्ष 2009 में यूपीए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कौशल नीति की घोषणा की थी और राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड का गठन किया था, जिसके उपरांत भी कुछ खास सुधार होता हुआ नहीं दिखा। भारत, विश्व भर में सबसे बड़ी कार्यशील आबादी (15-59 वर्ष) वाला दूसरा देश है, अत: इस जन समूह को कौशलयुक्त बनाना, देश की संवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जरूरी है कि उन्हें उत्पादक बनाने के लिए इस आयु वर्ग को पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

प्रमुख नौकरी सर्जक और नियोक्ता होने के नाते, निजी क्षेत्र के पास कौशल विकास कार्यक्रमों के दायरे गुणवत्ता और स्थिरता को प्रभावित करने की क्षमता है। वह न केवल औपचारिक बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र के लिए भी समान रूप से इन कौशल प्रशिक्षितों को रोजगार और आजीविका से जोड़ने में सक्षम है।

वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा मोटे तौर पर एक कल्याणकारी दृष्टिकोण के स्थान पर एक मांग आधारित दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रही है। विभिन्न महत्वाकांक्षी कौशल विकास पहलों के साथ, निजी क्षेत्र को पारिस्थितिकी को कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

प्रमुख नौकरी सर्जक और नियोक्ता होने के नाते, निजी क्षेत्र के पास कौशल विकास कार्यक्रमों के दायरे गुणवत्ता और स्थिरता को प्रभावित करने की क्षमता है। वह न केवल औपचारिक बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र के लिए भी समान रूप से इन कौशल प्रशिक्षितों को रोजगार और आजीविका से जोड़ने में सक्षम है। हालांकि, कुछ उद्योगों के अलावा निजी क्षेत्र ने जरूरत के मुताबिक हमारे कर्मचारियों को कुशल और प्रशिक्षित करने में निवेश नहीं किया है। दुनिया भर के ज्यादातर देशों में, जहां व्यावसायिक कौशल बहुत ज्यादा स्वीकार किए गए हैं, उद्योग ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप में कौशल विकास के लिए योगदान दिया है। इस क्षेत्र में कुशल श्रम शक्ति की एक उपभोक्ता के रूप में गुणवत्तापूर्ण ज्ञान की एक गैर लाभ सुविधा के रूप में या शिक्षा प्रदान करने के लिए एक लाभ उद्यम के रूप में, आदि कई भूमिकाएं हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र निभाते हैं।

निजी क्षेत्र, एक उपभोक्ता के रूप में अपनी पहली भूमिका उपलब्ध जनशक्ति को उपयुक्त कौशल में प्रशिक्षित कर और अंत में उन्हें रोजगार प्रदान करके लाभान्वित कर, निभा सकते हैं। एक गैर लाभ कार्यसुविधा के रूप में, कंपनियां, समाज को धन देकर और निवेश के माध्यम से उसे वापस कर सकती हैं। एक लाभ उद्यम के रूप में वे स्कूलों, प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों का निर्माण कर एक निश्चित मूल्य पर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

ऐसे कई तरीके हैं जिससे कि निजी क्षेत्र, भारत में कौशल विकास परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं।

- **उद्योग की मांग का पूर्वानुमान:** निजी क्षेत्र की भूमिका उद्योगों को मांग के मुताबिक बेहतर कुशल जनशक्ति की आंपूर्ति करने की योग्यता से निर्धारित होती है। चूंकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की (वेतनभोगी, संविदा, मजदूरी पर आधारित) नौकरियां उत्पन्न करता है और उनका उपयोग करता है। अत: उसे उत्पन्न होने वाली मांग के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वह अपने उपयोग के लिए प्रशिक्षित, रोजगारपरक, कुशल जनशक्ति की एक संसाधन स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। नौकरी में भूमिकाओं, मजदूरी, स्थानों और संख्याओं पर निजी क्षेत्र के माध्यम से विशेष जानकारी, प्रशिक्षण प्रदाताओं को उसी के हिसाब से उनके लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने में सक्षम बनाता है और उद्योग की ओर से की गई मांग के मुताबिक कौशल/ विशेषज्ञता प्रदान किया जाना सुनिश्चित करता है। इससे एक उपयुक्त प्रतिभा संपन्न कार्य बल तैयार करने में सहूलियत होती है। इससे नौकरी और कौशल के बीच असंगतता में कमी आती है।
- **गुणवत्ता और औद्योगिक मानदंड की स्थापना:** मौजूदा नौकरियों में कौशल अंतर की पहचान करने और राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एनओएस) के माध्यम से मौजूदा और नई नौकरी में भूमिकाओं का विकास करने और उन्हें मान्यता देने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु गुणवत्ता मानकों की स्थापना करने में निजी क्षेत्र अपना योगदान कर सकते हैं।
- **प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी:** सभी निजी कंपनियों के पास प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पहुंच, जानकारी और विशेषज्ञता या इन-हाउस क्षमता नहीं है। उन्हें अपने मानव संसाधन आवश्यकता को अद्यतन करने और अपनी जरूरतों के लिए एक

निजी क्षेत्र, एक उपभोक्ता के रूप में अपनी पहली भूमिका उपलब्ध जनशक्ति को उपयुक्त कौशल में प्रशिक्षित कर और अंत में उन्हें रोजगार प्रदान करके लाभान्वित कर, निभा सकते हैं। एक गैर लाभ कार्यसुविधा के रूप में, कंपनियां, समाज को धन देकर और निवेश के माध्यम से उसे वापस कर सकती हैं।

कौशल, नौकरी और सशक्तीकरण

विकास की ओर भारतीय महिलाओं की छलांग

दीनदयाल अंत्योदय योजना

- ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिला स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना।
- 3045 प्रखंडों में फैले 1,76414 गांवों में 26 लाख स्वयं सहायता समूह संगठित/समृद्ध किए गए।

स्टैंड अप इंडिया

- अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन
- पांच सौ करोड़ रुपये का आबंटन

प्रशिक्षण

- वर्ष 2015-16 में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी संस्थान ने 7247 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया
- पिछले दो वर्षों में एकीकृत कौशल विकास योजना के तहत 2.69 लाख महिलाओं में से 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण

नौकरी

- 2015-16 में सबसे अधिक नौकरी महिलाओं की भागीदारी मनरेगा में
- मिड डे मील योजना में 25.74 लाख रसोई या सह सहायता में से 90% से अधिक महिलाएं हैं

प्रतिभा पाइपलाइन तैयार करने के लिए लगातार प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ गठजोड़ करना चाहिए।

- **नौकरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता के लिए उद्योग को सुगम बनाना:** किसी भी चुने हुए कौशल में प्रशिक्षण और विशेषज्ञता के उच्च स्तर को पाने के लिए उद्योगों से जुड़कर और अपने हाथ से व्यावहारिक प्रशिक्षण व अनुभव प्राप्त करने के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ रही है। निजी क्षेत्र को बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं को नौकरी पर प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता (अप्रैंटिसशीप) के अवसर मुहैया कराने के लिए अपने दरवाजे खोल देने चाहिए।
- **कौशल विकास कार्यक्रमों की दिशा में सीएसआर कोष का उपयोग:** निजी क्षेत्र के पास व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करने के लिए अपेक्षित धन है। 2 प्रतिशत सीएसआर मंजूरी के साथ, कंपनियों को इस कोष का उपयोग कौशल विकास कार्यक्रमों में रचनात्मक निवेश करने के लिए करना चाहिए।
- **प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे में निवेश:** कंपनियां प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ साझेदारी कर बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, प्रौद्योगिकी और शिक्षा शास्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों कौशल प्रशिक्षण प्रदान पर खर्च कर सकते और अनुपूरक बन सकते हैं। वे विशेष प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं /उपकरण के लिए भी धन मुहैया करा सकते हैं या उसे सस्ता कर सकते हैं, जिसमें प्रशिक्षण साझीदारों के लिए निवेश करना बहुत महंगा साबित हो सकता है।

क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी), प्रशिक्षण प्रदाताओं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और सरकारी निकायों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र किसी भी कौशल प्रशिक्षण पहल की सफलता को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित कर सकता है।

एक उभरती सेवा संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी प्रतिस्पर्धा में बढ़त के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी के साथ हमारे विकास को बढ़ावा देने के लिए, एक कुशल कार्यबल रखने के महत्व का एहसास करने हेतु, यह महत्वपूर्ण है। कौशल और शिक्षा से शिक्षार्थी के रोजगार में वृद्धि होगी। अर्जित ज्ञान के साथ, श्रमिक, भारत की प्रतिस्पर्धा में बढ़त निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता में योगदान देंगे।

विभिन्न सुधारों, नीति में परिवर्तन और बेहतर वित्तीय परिव्यय जो संभवत: देश को एक ज्ञान स्थली में बदल सकता है, के माध्यम से इसमें सरकार द्वारा एक स्पष्ट प्रयास किया गया है। ऐसे समय में, निजी क्षेत्र की भागीदारी और भूमिका बिल्कुल अपरिहार्य है और कौशल विकास के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा इसी तरह के प्रयासों के जरिए समर्थन किया जाना चाहिए। यह समय भारत के निजी क्षेत्र के लिए है, कि वे इन प्रमुख सरकारी पहलों से नजदीकी से जुड़कर इन्हें आगे ले जाएं। हमारी जनसांख्यिकी, हमें दुनिया को कार्य बल प्रदान करने में बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम निजी क्षेत्र और सरकार के बीच एक उत्कृष्ट भागीदारी का निर्माण करें। ❑